

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2018—श्रावण 19, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/1-2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015/46/2017-AIS (I)-A, दिनांक 06-04-2018 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित अधिकारी को राज्य शासन एतद्वारा उन्हें, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित पद पर

अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	नवीन पदस्थापना
1.	श्री भरत लाल बंजारे	06-04-2018	उप सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार समाज कल्याण विभाग.

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2018

क्रमांक ई-1-15/2017/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

श्री एस. भारतीदासन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक ई-1-16/2004/1/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/23/2018-एआईएस (I) दिनांक 26-06-2018 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (2) के अंतर्गत डॉ. नितिन गौर, भा.प्र.से. (सीजी : 2016) की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक बी-1-1/2018/एक/4.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-6-2018 द्वारा श्री मनीष मिश्रा (रा.प्र.से. पी-15 कनिष्ठ श्रेणी), डिप्टी कलेक्टर, रायपुर को स्थानांतरित करते हुए, उन्हें डिप्टी कलेक्टर, जिला-मुंगेली के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त पदस्थापना आदेश में संशोधन करते हुए, श्री मनीष मिश्रा (रा.प्र.से. पी-15 कनिष्ठ श्रेणी), डिप्टी कलेक्टर को सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2018

क्रमांक ई 7-49/2004/एक-2.—श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997), सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंधन संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, सचिव, खनिज साधन विभाग, अध्यक्ष, सीएमडीसी, सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन परियोजनाएं) को दिनांक 21-06-2018 से दिनांक 27-06-2018 तक (कुल 07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार सिंह आगामी आदेश तक सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंधन संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, सचिव, खनिज साधन विभाग, अध्यक्ष, सीएमडीसी, सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल लाईन परियोजनाएं) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश काल में श्री सुबोध कुमार सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुबोध कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरज लाल, अवर सचिव।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-19-47/2011/25-2.—छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 3 के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 01-07-2015 द्वारा डॉ. सियाराम साहू को तीन वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था।

और यतः डॉ. सियाराम साहू की अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पद की तीन वर्ष की अवधि दिनांक 03 जुलाई 2018 को पूर्ण हो गई है। अतएव राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त डॉ. सियाराम साहू को दिनांक 28 जुलाई 2018 से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पद पर नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, संयुक्त सचिव।

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 1-5/2018/13/1.—इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका-76 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री शिवराज सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 01 वर्ष अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड में डायरेक्टर तथा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है।

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक 1020/आर-95/2017/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती तृप्ति सिन्हा, को उक्त कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक महिला डायरेक्टर, नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक 1022/आर-95/2017/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती तृप्ति सिन्हा, को उक्त कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक महिला डायरेक्टर, नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक 1024/आर-95/2017/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती तृप्ति सिन्हा, को उक्त कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक महिला डायरेक्टर, नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 7-23/2018/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र, जिला कोण्डागांव का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :—

अनुसूची

बड़े कनेरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम बड़े कनेरा एवं जरे बेंदरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
- पश्चिम में : ग्राम बोलबोला, करंजी एवं बड़े कनेरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
- दक्षिण में : ग्राम कुकाड़गारकापाल एवं बड़े कनेरा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
- पूर्व में : ग्राम बड़े कनेरा एवं कमेला ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बलौदाबाजार के निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

- (1) रवान (2) हथबन्द (3) रावन (4) सोनाडीह (5) रिसदा (6) गिरौदपुरी (7) हिरमी
(8) खपराडीह.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2018

क्रमांक एफ 1-02/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. सिंह, भा.व.से. (1983) प्रधान मुख्य वन संरक्षक को शीर्षस्थ वेतनमान (Pay level 17 Apex Scale : Rs. 2,25,000 Fixed) में चयन करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (Head of Forest Force) छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 1-05/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. के. कटकवार, भा.व.से. (1998) वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर को दिनांक 10-05-2016 से मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान : अनुसूची-III के वेतन मेट्रिक्स लेबल 14: वेतन रु. 1,44,200-2,18,200) के पद पर पदोन्नत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/7364/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	केसालडबरी, प.ह.नं. 03/कृषकों की संख्या 01	0.325 हे.	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के टाटेकसा-खैरी मार्ग पर स्थित टाटेकसा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 28-08-2018 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-केसालडबरी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के टाटेकसा-खैरी मार्ग पर स्थित टाटेकसा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	-
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन तथा परिवहन में सुगमता, बारहमासी मार्ग की उपलब्धता.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/7366/भू-अर्जन/2018.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	टाटेकसा, प.ह.नं. 03/कृषकों की संख्या 04	0.316 हे.	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के टाटेकसा-खैरी मार्ग पर स्थित टाटेकसा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 21-08-2018 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-टाटेकसा नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोक निर्माण विभाग (सेतू निर्माण), राजनांदगांव के टाटेकसा-खैरी मार्ग पर स्थित टाटेकसा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	-
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन तथा परिवहन में सुगमता, बारहमासी मार्ग की उपलब्धता.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/7368/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	पीपरखार, प.ह.नं. 27/कृषकों की संख्या 01	0.016 हे.	जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव के मोंगरा परियोजना के अंतर्गत दांयी तट शाखा नहर निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 25-08-2018 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-पीपरखार नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव के मोंगरा परियोजना के अंतर्गत दांयी तट शाखा निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	-
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई रकबे में वृद्धि
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/7370/भू-अर्जन/2018.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	पोसवार, प.ह.नं. 10/कृषकों की संख्या 02	0.853 हे.	जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव के मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-08-2018 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-पोसवार पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव के मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	-
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई रकबे में वृद्धि
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

महासमुंद, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्रमांक/37/क/भू-अर्जन/06/अ/82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बसना	बुटीपाली प.ह.नं. 09	26.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कसडोल जिला बलौदा- बाजार-भाटापारा.	बिला नाला जलाशय योजना के डूबान में आने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 31 जुलाई 2018

क्रमांक/38/क/भू-अर्जन/07/अ/82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बसना	हेडसपाली प.ह.नं. 09	12.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कसडोल जिला बलौदा- बाजार-भाटापारा.	बिला नाला जलाशय योजना के डूबान में आने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2018

क्रमांक 97/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अमसेना प.ह.नं. 38	0.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर
(1)
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2018

क्रमांक 72/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-चनाडोंगरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.233 हेक्टेयर

593	0.081
750	0.012
1353	0.032
608	0.012
609	0.016
610	0.049
623	0.057
622	0.032
619	0.012
655	0.032
611	0.032
624	0.028
625/1	0.109
631	0.113
632	0.032
634	0.032
633	0.024
656	0.020
657	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
654	0.052	1349	0.121
673	0.061	1350	0.004
674/1	0.057	1352	0.024
674/3	0.020	1354	0.057
713	0.024	1336	0.049
709/2,	0.040	1337/1	0.036
709/4		1876	0.012
743	0.016	1877	0.008
744	0.040	1337/2	0.045
746	0.012	1333	0.020
748	0.012	1335	0.040
747	0.028	1357	0.020
751	0.008	1334	0.040
1022	0.020	1358	0.121
752/2	0.019	1359	0.008
749	0.077	1362/3	0.020
774	0.036	1360	0.077
777	0.008	1786	0.024
772	0.057	1361	0.028
811	0.008	1545	0.036
773	0.012	1542	0.089
809	0.089	1541	0.028
804	0.040	1537	0.089
805	0.056	1543	0.040
803/3,	0.049	1536	0.061
806		1535	0.004
1233	0.077	1525/1	0.004
1236	0.032	1525/2	0.125
1242	0.089	1524	0.069
813	0.052	1732	0.008
812/2	0.024	1523	0.036
808	0.045	1733,	0.008
818	0.028	1735	
1224	0.032	1745	0.024
289	0.049	1740	0.061
1232	0.049	1741	0.101
1230	0.024	1742	0.077
1867	0.008	1743	0.081
1231	0.036	1744/1	0.028
1235	0.012	1744/2	0.020
1239	0.057	1784,	0.024
1240	0.008	1752	
1241	0.020	1785	0.057
1347	0.032	1787	0.024
1229	0.008	1788/2	0.061
1225	0.081	1832	0.028
1345	0.040	1831/6	0.036
1348	0.028		

(1)	(2)	(1)	(2)
1831/7	0.020	1149/2	0.073
1831/5	0.008	1165	0.020
1831/2	0.101	1151	0.012
1831/3	0.073	1156	0.016
1830	0.040	1155	0.040
1803/2	0.101	1153	0.020
1829/2d	0.040	1109	0.040
1828	0.008	1106	0.028
1827	0.069	1105	0.016
1826/2	0.065	1107/2	0.028
1865	0.020	1002	0.004
1825/1	0.061	1003	0.016
1825/2	0.154	1004/1,	0.028
1870/2	0.085	1004/2	
1878	0.065	1005/1	0.012
1875/1	0.052	1298/2	0.040
1868/1	0.109	1106	0.020
1879	0.032	1021	0.040
1875/5	0.045	1537	0.028
1875/2	0.182	1538	0.012
1888/2	0.097	1539	0.036
1875/3	0.073	1362/6	0.024
1875/4	0.045	1365/1	0.024
77	0.065	1369,	0.068
76/1	0.198	1370,	
76/2	0.036	1519/1	
65/4	0.129	1371	0.028
65/6	0.101	1380	0.113
65/5	0.121	1373	0.032
65/3	0.134	1374	0.032
65/2	0.202	1375	0.008
66/1	0.109	1377	0.040
66/2	0.125	1512/1	0.024
64	0.004	1311/1	0.073
63/1	0.004	1311/2	0.052
1364	0.028	1310	0.020
816	0.028	1362/4	0.016
817	0.032	1080	0.032
1228	0.024	1297	0.049
1245	0.008	1298/1	0.012
1223	0.028	1300/1	0.061
1145/2	0.028	1299/4	0.045
1146/1	0.032	1301/1	0.085
1166	0.008	1087	0.048
1146/2	0.024	1084/2	0.012
1163	0.008	1079	0.048
1167/1	0.012	1088	0.020
1149/1	0.077	1081	0.032
1381/2	0.174		

	(1)	(2)	(1)	(2)
	1738	0.020	477/1,	0.020
	1739	0.012	481	
			479	0.016
योग	213	9.233	480/1 ख	0.012
			493/1	0.089
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार			493/2	0.073
बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.			480/4	0.045
			480/2	0.049
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी			480/1 क	0.069
(राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.			448	0.040
			योग	22 1.119

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-केसला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.119 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
588/2	0.045
588/1	0.057
619/2	0.045
585/1	0.040
543	0.109
545	0.077
547	0.045
548	0.065
497/2	0.073
496	0.065
494/1	0.073
494/2	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के केसला माइनर 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्रमांक 09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-अमेरीकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.187 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57	0.336
56/3	0.012
56/4	0.028
58/1	0.012

(1)	(2)	बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2018	
58/2	0.012	<p>क्रमांक 60/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला-बिलासपुर</p> <p>(ख) तहसील-तखतपुर</p> <p>(ग) नगर/ग्राम-मेडपार</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.316 हेक्टेयर</p>	
54	0.129		
59/3	0.024		
61/6	0.077		
61/39	0.085		
61/22	0.008		
61/40	0.004		
61/17	0.097		
61/42	0.057		
61/10	0.053		
61/3	0.117		
61/38	0.012		
61/37	0.024		
61/36	0.024		
61/35	0.028		
72/5	0.008		
103/14	0.040	खसरा नम्बर	रकबा
103/15	0.040		(हेक्टेयर में)
71/1	0.146	(1)	(2)
72/2	0.069		
72/4	0.057	323/15,	0.053
72/18	0.016	323/16	
72/19	0.053	65/3	0.024
103/12	0.045	66	0.049
100/7	0.053	67	0.016
100/8	0.166	70/4	0.036
99/12	0.040	64/5	0.032
100/6	0.045	64/6	0.105
100/3	0.109	64/7	0.036
100/10	0.012	69/1	0.061
99/13	0.081	69/2	0.036
99/9	0.032	63/1	0.024
99/10,	0.016	70/3	0.085
99/7		73	0.113
99/3	0.020	74/2	0.016
		70/2	0.004
		70/6	0.016
		74/1	0.032
		72/2	0.061
		72/5	0.069
		112/34	0.028
		103/1	0.012
		76	0.065
		77/1	0.040
योग	39	2.187	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अमेरीकापा माईनर नहर निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.			

(1)	(2)	बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2018																															
112/3, 112/4 88 112/36 112/31 112/17 112/16 112/13 112/14 75/1 90 85/2, 89/5 89/6 87 101/1 101/3 295/6 102/2 103/2, 103/3 107/1 104/4 293/3 293/1 294 295/2 295/3 292/1 300 112/6	0.247 0.032 0.032 0.028 0.040 0.081 0.028 0.020 0.016 0.028 0.053 0.049 0.032 0.036 0.028 0.016 0.020 0.057 0.032 0.024 0.040 0.020 0.101 0.097 0.016 0.073 0.049 0.036	<p>क्रमांक 82/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला-बिलासपुर</p> <p>(ख) तहसील-तखतपुर</p> <p>(ग) नगर/ग्राम-मेण्ड्रा</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.485 हेक्टेयर</p> <table><tr><th>खसरा नम्बर</th><th>रकबा (हेक्टेयर में)</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th></tr><tr><td>701/11</td><td>0.186</td></tr><tr><td>701/19</td><td>0.004</td></tr><tr><td>701/29</td><td>0.032</td></tr><tr><td>701/30</td><td>0.020</td></tr><tr><td>701/31</td><td>0.061</td></tr><tr><td>701/32</td><td>0.023</td></tr><tr><td>701/33</td><td>0.045</td></tr><tr><td>701/34</td><td>0.022</td></tr><tr><td>701/35</td><td>0.021</td></tr><tr><td>701/36</td><td>0.022</td></tr><tr><td>701/37</td><td>0.033</td></tr><tr><td>701/38</td><td>0.016</td></tr><tr><td>योग</td><td>12 0.485</td></tr></table>		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	701/11	0.186	701/19	0.004	701/29	0.032	701/30	0.020	701/31	0.061	701/32	0.023	701/33	0.045	701/34	0.022	701/35	0.021	701/36	0.022	701/37	0.033	701/38	0.016	योग	12 0.485
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)																																
(1)	(2)																																
701/11	0.186																																
701/19	0.004																																
701/29	0.032																																
701/30	0.020																																
701/31	0.061																																
701/32	0.023																																
701/33	0.045																																
701/34	0.022																																
701/35	0.021																																
701/36	0.022																																
701/37	0.033																																
701/38	0.016																																
योग	12 0.485																																
योग	55 2.344	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.																															

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 8 जून 2018

क्रमांक/1/अ-82/2018-19.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-खोपा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
643	0.090
645	0.090
649	0.240
650	0.120
योग	04 0.540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोपा-लोधिमा मार्ग पर रेहण्ड नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण खोपा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक 12594/अ-82/2018.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंडीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-लरला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
365/1 ड	0.405
योग	01 0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांगो बांध के डूब में अर्जित हो जाने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंडीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/3116.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5971-5972 रायपुर दिनांक 30-12-2016 द्वारा श्री जोगेन्द्र नायक, संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मण्डी समिति अभनपुर, जिला-रायपुर भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 996 दिनांक 19-06-2018 द्वारा श्री बसंत कुमार कन्द्रा, कृषि विकास अधिकारी अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर, जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, चूंकि विकासखण्ड अभनपुर में श्री भोलाराम लाउत्रे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पदस्थ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री जोगेन्द्र नायक, संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर श्री भोलाराम लाउत्रे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अभनपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अभनपुर, जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

नया रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2018

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2018/886.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नियम 1961 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो नीचे लिखित अनुसार दिनांक 24-09-2018 से 28-09-2018 तक होगी :—

भाग-एक

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम	24-09-2018	सोमवार	संक्षेपिका तथा प्रारूप (पुस्तक रहित)	3.00 घंटे प्रातः 11.00 से 2.00 बजे
2.	द्वितीय	25-09-2018	मंगलवार	मूलभूत नियम, सिविल लेखा विनियम इत्यादि (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रातः 11.00 से 1.30 बजे
3.	तृतीय	26-09-2018	बुधवार	लेखा परीक्षा तथा लेखा संहिताएं (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रातः 11.00 से 1.30 बजे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	चतुर्थ-अ	27-09-2018	गुरुवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे प्रातः 11.00 से 12.30 बजे
5.	चतुर्थ-ब	28-09-2018	शुक्रवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (व्यावहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे प्रातः 11.00 से 1.30 बजे

भाग-दो

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम-अ	24-09-2018	सोमवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित)	1.30 घंटे दोपहर 11.00 से 12.30 बजे
2.	प्रथम-ब	25-09-2018	मंगलवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यावहारिक) (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे दोपहर 11.00 से 01.30 बजे
3.	द्वितीय	26-09-2018	बुधवार	भारत का संविधान (पुस्तक सहित)	3 घंटे दोपहर 11.00 से 02.00 बजे
4.	तृतीय	27-09-2018	गुरुवार	वाणिज्यिक बहीखाता (पुस्तक रहित)	2 घंटे दोपहर 11.00 से 01.00 बजे
5.	चतुर्थ	28-09-2018	शुक्रवार	स्थानीय नियम तथा लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता (पुस्तक सहित)	2.30 घंटे 11.00 से 01.30 बजे

हस्ता./-
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th July 2018

No. 815/Confdl./2018/II-2-4/2002 (Part-II).—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry order No. 269/Confdl./2016/II-2-4/2002 dated 07-04-2016, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Ku. Saroj Nand Das	04-06-2018
2.	Shri Santosh Kumar Aditya	13-06-2018

(1)	(2)	(3)
3.	Shri Sanjeev Kumar Tamak	18-06-2018
4.	Shri Khilawan Ram Rigri	18-06-2018
5.	Ku. Sanghratna Bhatpahari	18-06-2018

Bilaspur, the 19th July 2018

No. 817/Confdl./2018/II-2-4/2002 (Part-II).—The following Officiating District Judges of Higher Judicial Service are, hereby, issued Certificate in terms of sub-rule (5) of Rule 9 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)
1.	Shri Gregory Tirkey
2.	Shri Vinod Kumar Dewangan
3.	Smt. Prisilla Paul Horo

Bilaspur, the 19th July 2018

No. 819/Confdl./2018/II-3-2/2002 (Part-II).—The following Judicial Officers of Lower Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry order No. 228/Confdl./2016/II-3-2/2002(Pt.-II) dated 18-03-2016, are, hereby confirmed in Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Confirmation (3)
1.	Smt. Sarojani Janardan Khare	04-06-2018
2.	Shri Shyam Kumar Sahu	13-06-2018
3.	Smt. Anita Dhruw	18-06-2018
4.	Ku. Rajeshwari Suryawanshi	18-06-2018
5.	Shri Vijendra Sonwani	18-06-2018

Bilaspur, the 19th July 2018

No. 821/Confdl./2018/II-3-2/2002 (Part-II).—The following probationary Civil Judges Class-II of Lower Judicial Service, are hereby, issued certificate in terms of sub-rule (5) of Rule 11 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

S. No. (1)	Name of Officer (2)
1.	Smt. Neha Yati Mishra
2.	Shri Dilli Singh Baghel
3.	Ku. Apurva Khare
4.	Shri Bhaskar Mishra

(1)	(2)
5.	Shri Praveen Mishra
6.	Smt. Prateeksha Sharma
7.	Ku. Mayura Gupta
8.	Ku. Astha Yadav
9.	Smt. Nidhi Sharma
10.	Ku. Tanu Shree Gavel
11.	Ku. Deepti Singh Gaur
12.	Shri Pallve Raghuvanshi
13.	Shri Bhupesh Kumar Basant
14.	Ku. Chetna Thakur
15.	Ku. Seema Kanwar
16.	Ku. Jasvinder Kaur Ajmani
17.	Shri Aslam Khan
18.	Shri Anand Kumar Singh
19.	Shri Shiv Prakash Tripathi
20.	Shri Ramesh Kumar Chauhan
21.	Shri Losesh Kumar
22.	Shri Girish Pal Singh
23.	Ku. Manju Lata Sinha
24.	Ku. Barkha Rani Kasar
25.	Shri Gulapan Ram Yadav
26.	Ku. Amita Jaiswal
27.	Shri Satyanand Prasad
28.	Ku. Suman Dhruw
29.	Ku. Rupal Agrawal
30.	Ku. Khileshwari Sinha
31.	Smt. Amrita Dinesh Mishra
32.	Shri Bhagwan Das Panika
33.	Ku. Neha Usendi
34.	Shri Anant Deep Tirkey
35.	Ku. Mrinalini Katulkar
36.	Shri Devashish Thakur
37.	Ku. Bhawana Nayak
38.	Ku. Sweta Baghel
39.	Ku. Anita Koshima
40.	Shri Bhavesh Kumar Watti
41.	Ku. Deepa Suchita Tirkey
42.	Shri Vivek Netam
43.	Shri Puneet Ram Gurupanch
44.	Ku. Seema Jagdalla
45.	Shri Anil Kumar Chauhan
46.	Smt. Kanchan Lata Achala
47.	Smt. Shanti Prabhu Jain
48.	Ku. Anjali Singh
49.	Smt. Deepti Lakra

Bilaspur, the 20th July 2018

No. 823/Confdl./2018/II-2-1/2018.—Ku. Sunita Sahu, III Additional District and Sessions Judge, Jagdalpur is, hereby, assigned the additional charge of the Court of Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Jagdalpur until further orders.

Bilaspur, the 20th July 2018

No. 825/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby, assigned additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Smt. Kiran Tripathi, I Civil Judge Class-I & C.J.M., Mahasamund.	Labour Court, Mahasamund
2.	Shri Sumit Kapoor, III Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Raipur.	Labour Court No.-1, Raipur
3.	Shri Shailesh Sharma, II Civil Judge Class-I, Raipur	Labour Court No.-2, Raipur

Bilaspur, the 20th July 2018

No. 6784/S & A Cell/2018.—In continuation with earlier notification No. 3792 dated 16-04-2018 and in exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 (as amended from time to time) and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court in its order dated 04-01-07 passed in C.A. 1867/06 (Malik Mazhar Sultan and another V/s U.P. Public Service Commission & ors.), the High Court of Chhattisgarh re-notifies the anticipated vacancies in respect of district Judge (Entry Level) as under :—

a)	By Promotion in accordance with Rule 5 (1) (a)	35 posts
b)	By promotion through limited competitive examination in accordance with Rule 5 (1) (b).	05 posts
c)	By direct recruitment from the Bar in accordance with Rule 5 (1) (c).	22 posts
		(Current year :- UR-10, SC-01, ST-03, OBC-Nil). (Carried forward of the year 2017:- UR-7) (Backlog of year 2017 :- SC-1)

Bilaspur, the 20th July 2018

No. 6786/S & A Cell/2018.—In continuation with earlier notification No. 3181/S & A Cell/2018 dated 31-03-2018 and in exercise of powers conferred by sub rule (2) of rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 (as amended time to time) and in view of the directions of Hon'ble the Supreme Court in its order dated 04-01-2017 passed in C.A. 1867/2006 (Malik Mazhar Sultan and

Another V/s U.P. Public Service Commission & Ors.), the High Court of Chhattisgarh re-notifies the vacancies in respect of Senior Civil Judge as under :—

a)	Promotion in accordance with sub rule 2 of Rule 5 of Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006.	14 posts
----	---	----------

Bilaspur, the 20th July 2018

No. 6800/Checker/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Ku. Jasvinder Kaur Ajmani, Judicial Magistrate First Class, Dallirajhara, District-Balod to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of Hon'ble the High Court,
NEELAM CHAND SANKHALA, Registrar General.
